भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2210

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन</u>

2210. श्री राजमणि पटेल:

डॉ. एल. हनुमंतय्या:

श्रीमती फूलो देवी नेतम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत पर राजसहायता देने का विचार रखती है ताकि संसाधन की मांग सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार नि:शुल्क विद्युत परिषण के अतिरिक्त और भी लाभ प्रदान कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता बायोगैस जैसे अन्य स्रोतों की जगह हाइड्रोजन ऊर्जा को चुनें;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की समय-सीमा तथा अनुमानित लागतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ): माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने तदनुसार एक मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है।

विद्युत मंत्रालय की दिनांक 17 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. 23/02/2022-आर एंड आर में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत में कमी लाने के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा, मिशन के प्रारूप में अन्य के साथ-साथ मांग सृजन, स्वदेशी निर्माण के लिए सहायता, अनुसंधान एवं विकास, प्रायोगिक परियोजनाएं तथा समर्थकारी नीतियों एवं नियमनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित उपायों से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हरित हाइड्रोजन की लागत में कमी आने की संभावना है।

मिशन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*****